

15 हजार महिलाओं को मिलेगा रोजगार

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत राज्य सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत सरकार ने 47 करोड़ रुपये की लागत से 14 इन्क्यूबेशन सेंटर/कामन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश में पूरी कर दी है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अनुमान है कि इस साल इन केंद्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 15 हजार महिलाओं को रोजगार मिलेगा।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने 10 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपये की धनराशि

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में 14 इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना
- स्वयं सहायता समूहों के लिए 30 करोड़ स्वीकृत



आवंटित की है। यह राशि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदान की गई है। यह कदम न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि उनकी उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दे रहा है।

पीएमएफएमई योजना के तहत एमआइएस वेब पोर्टल पर अब तक 46,897 उद्यमियों का पंजीकरण किया गया है जिनमें से 32,176 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बैंकों ने

ज्वार खरीद में टूटा पिछले साल का रिकार्ड

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : प्रदेश सरकार ने ज्वार खरीद में पिछले साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। सरकार ने 31 दिसंबर तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 104.32 प्रतिशत ज्वार खरीदा है। कुल 10704 किसानों से इस वर्ष 46942.15 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद हुई है, जबकि पिछले वर्ष 13340.30 मीट्रिक टन खरीद हुई थी। सरकार ने ज्वार किसानों को 140.76 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान भी कर दिया है। इस वर्ष ज्वार खरीद का लक्ष्य 45 हजार मीट्रिक टन निर्धारित था। ज्वार खरीद को बढ़ावा देने के साथ ही सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया था। ज्वार खरीद पहली अक्टूबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक हुई। यह खरीद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर-देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर व जालौन में की गई।

13,933 परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया है।